

27-02-18

L.T.I. श्यामलाल

पत्रावली पेश हुई अप्रार्थी श्यामलाल उपस्थित/अप्रार्थी ने माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूक के न्यायालय के विविध फौजदारी प्रकरण सं० 489/2015 अनुवानी श्रीमती रूकमणीदेवी बनाम श्यामलाल अन्तर्गत धारा 125 दंड प्र०सं० के निर्णय दिनांक 03-02-2018 की प्रमाणित प्रति पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध उपरोक्त अनुवानी प्रकरण, जो भ्रम-पोषण से ही सम्बन्धित है, में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णित किया जाकर मुझ अप्रार्थी को पन्द्रह सौ रुपये प्रतिमाह आदेश जारी होने की दिनांक से प्रार्थिनी श्रीमती रूकमणीदेवी को अदा करने का आदेश दिया है, जिसको देना मैं स्वीकार करता हूँ। अतः अब इस प्रकरण को इसी स्तर पर ड्रॉप किया जावे। निर्णय की प्रतिलिपि शामिल पत्रावली की जाकर अवलोकन किया गया। माननीय न्यायालय ने अपने प्रकरण सं० 489/2015 अन्तर्गत धारा 125 दंड प्र०सं० जो भ्रम-पोषण से ही सम्बन्धित है, में दिनांक 03-02-18 को निर्णय जारी कर अप्रार्थी को पन्द्रह सौ रुपये प्रतिमाह आदेश की दिनांक से प्रार्थिनी श्रीमती रूकमणीदेवी को अदा करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय/आदेश में यह भी अंकित किया है कि उक्त भ्रम-पोषण की रकम प्रार्थिनी द्वारा अप्रार्थी से अन्य किसी अधिविवयम के तहत प्राप्त कर रही होती उसमें यह राशि समायोजित की जा सकती। निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस प्रार्थिनी के प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूक के बड़े धारा 125 दंड प्र०सं० के तहत विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

होवा अप्रार्थी को पन्द्रहसौ रुपये प्रतिमाह कीमती करवर्षी
होवी को अदा करने करण-पोषण राशि के रूप में अदा करने
का आदेश दिया जा चुका है जिसे अप्रार्थी की सहमति
है। इसलिए इस न्यायालय के इस प्रार्थना पत्र जो करण
पोषण से सम्बन्धित है, में प्रत्यक्ष से कोई आदेश जारी
किये जाने का औचित्य नहीं है। अब इस फावली में
आगे कार्यवाही जारी रखने का भी कोई औचित्य नहीं है।
अतः प्रार्थनी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 अप्रिजावों
और वरिष्ठ नागरिकों का करण-पोषण और कल्याण अधिनियम
2007 का इसी स्तर पर दाय्य किया जा रहा है। आदेश खुले
न्यायालय में सुनाया गया। मिसल फँसल शुमार होवा
नम्बर से कम हो व जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

कार्यवाही पत्र आता पित्त एव
दस्तावेज अधिनियम 2007

सीमांतरी

प्राथमिक और से प्रार्थना पत्र को दे लिये अनुत्तर देत
प्राथमिक एव 75 दफ्तर वृत्त विद्यया विचार करिक है। जो
दोनों पत्रों के अन्तर्गत लगातार प्रार्थना पत्रों को देत है।
अतः प्रार्थना पत्रों को देत और प्रार्थना पत्रों को देत है।
अतः प्रार्थना पत्रों को देत और प्रार्थना पत्रों को देत है।